

सरकार के उद्योग बंदी, क्यू बंदी, वेबलवर्केंट कमिशनर, स्मल स्केल इंडस्ट्रीज विलडी की धीर उ० प्र० की सरकार धीर भूमि विकास बैंक को भी जानकारी दी है धीर मांग की है कि राजकोट में क्यू मार्क वाले डीजल इंजनों की मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार धीर उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक चालू रखे। इन के बारे में केन्द्रीय सरकार का उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश की सरकार धीर भूमि विकास बैंक को तुरन्त सूचना दे कि राजकोट (सौराष्ट्र) में बनते हुए डीजल प्रायल इंजनों की क्वालिटी (क्यू) मार्क की मान्यता (रिकगनीशन) चालू रखे धीर जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर किसानों को सस्ता डीजल इंजन देने की व्यवस्था अभी तक थी, इसे भ्रमल में चालू रखें।

गुजरात सौराष्ट्र के फूलछाव, लोक-मान्य, जनसत्ता, सदेश, गुजरात समाचार जयहिन्द वगैरह दैनिक प्रखबारों में प्रप्रलेख धीर समाचार के माध्यम से भी इसके लिए बहुत मांग की गई है।

डीजल प्रायल इजानियरिंग उद्योग को बचाने के लिए धीर क्यू क्वालिटी मार्क की मान्यता चालू रखने के लिए उद्योग मंत्रालय तुरन्त प्रबन्ध करे, ऐसी मेरी तन्न प्रार्थना है।

(iii) REPORTED HUNGER STRIKE BY LABOURERS OF CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION, NEW DELHI

**SHRI BALDEV SINGH JASROTHIA** (Jammu): A large number of poor food handling labour of the Central Ware-Housing Corporation Tekh Khand Depot (Okhla, New Delhi) were working in the Depot since its inception under the Contract Labour System which expired on 31st October, 1977 as per the contract Labour (Regulation and Abolishing Act of 1970). The labourers are on relay hunger strike in front of the Central

Warehousing Corporation from December 7th, 1977, with a further request to implement the direct payment system.

The wages of the labourers amounting to Rs. 50,000/- approximately, have not been paid besides restoration of all other rights, giving rise to a great unrest in the labour class and it can cause a deadlock besides other law and order situation and complications.

I appeal to the hon. Agriculture Minister and hon. Labour Minister to intervene and solve the problem with a further request that all other benefits to which the labourers are entitled may also be given to them.

A similar problem and situation flowing from the same set of factors is there at Jammu. These Ministers are requested to look into the matter as early as possible to avoid any grave situation which is apt to come out otherwise.

(iv) REPORTED DECISION AT THE CHIEF MINISTERS' CONFERENCE ABOUT ABOLITION OF OCTROI

**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मदतौर):** मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन राज्यों द्वारा प्राकृत्य समाप्ति पर केन्द्र द्वारा जो वित्तीय सहायता दिये जाने की बात कही गई थी उसके न दिए जाने पर यह महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जा 18 जनवरी 1977 को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ था केन्द्र सरकार की धीर मे परिषहन मंत्री द्वारा यह प्राश्वासन दिया गया था कि जो राज्य प्राकृत्य समाप्त करेगे उन्हें इससे जो बाटा होगा उस बाटे को पचास प्रतिशत अनुदान दे कर पूरा किया जाएगा, या यह पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में उस बाटे की पूर्ति हेतु प्रशदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र के इस प्राश्वासन के अनुकार प्राकृत्य समाप्त की गई धीर वित्तीय सहा-